समावेशन परक वृद्धि : वित्तीय शिक्षा की भूमिका*

श्यामला गोपीनाथ

मैं जानती हूं कि आप 'वित्तीय समावेशन' तथा वित्तीय समावेशन परक वृद्धि की नीति संबंधी समस्याओं में प्रतिध्वनित हो रहे विभिन्न मुद्दों पर यशस्वी वक्ताओं को सुन चुके हैं तथा विशेषज्ञों के सत्रों में भाग ले चुके हैं। मैं इसे समस्या क्यों कह रही हूं इसका कारण है कि एक ओर प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करता है कि सघउ में वृद्धि की महत्वाकांक्षा रखने के लिए तथा व्यापक रूप में आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक व्यापक आधार पर पहुंच अनिवार्य शर्त है; जबकि दूसरी ओर इस दिशा में उभर रही पहलें सर्वोत्तम रूप में छोटे-छोटे हिस्सों तक ही सीमित हैं। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, अनेक देश इस समस्या का समाधान पाने के लिए अंतिम छोर तक प्रयत्न कर रहे हैं। व्यापक स्तर पर, शायद हाल ही में यह क्षेत्र मुख्य क्षेत्र के वित्त में देखे गए शैक्षिक कठोरता का स्तर देख रहे हैं। यह शायद जिन मुद्दों की हम तलाश कर रहे हैं उनके आंतरिक स्वरूप के कारण भी हो सकता है। अधिकांश पहलें 'ढांचे के अंदर' समाधान खोजने की रही हैं जिनकी अपनी आंतरिक सीमाएं हैं। जब हम वित्तीय नवोन्मेषों तथा मुख्य धारा वाले वित्त में देखे गए उत्पादों के विस्फोट की बात करते हैं तो उस संदर्भ में तब यह मुद्दा ज्यादा मुखर हो जाता है।

इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए यह रोचक होगा कि पहले आम तौर पर वित्त के और विशेषकर बैंकिंग के अनुशासन के विकास पर नजर डाली जाए । कुछ दशकों पहले तक, वित्त का क्षेत्र स्वयं में, एक रूप से, 'आर्थिक क्षेत्र' का छोटा चचेरा भाई था और आस्ति मूल्यों, विशेषकर खरीदे बेचे गए स्टॉकों से शुरू होकर उससे संबंधित क्रांतिकारी विचारों और सिद्धांतों ने ही इस परिदृश्य को बदल दिया। परवर्ती शैक्षिक योगदानों ने विकल्पगत मूल्यनिर्धारणों ने डेरिवेटिव्स में क्रांति का शंखनाद कर दिया जिसने वास्तव में, वित्तीय आवश्यकताओं को तथा कंपनी और खुदरा क्षेत्र के कुछ घटकों को उपलब्ध विकल्पों को पण्य बना दिया। औद्योगिक मितव्ययिताओं में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए उनकी प्रतिक्रिया-स्वरूप वित्त के क्षेत्र में उपर्युक्त उन्नयन हुए हैं और उनके चारों ओर बनाए गए अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष लक्षित समूह को उद्देश्य बनाया गया। अधिकांश सिद्धांतों को क्रमिक रूप से व्यापक स्वीकृति मिली तथा भारत सहित सारे विश्व में अपनाए गए। अब हमें वित्तीय रूप से समावेशन परक वृद्धि को बढ़ाने में इसी प्रकार की क्रांति की जरूरत है।

तथापि भारत जैसे संश्लिष्ट देश की जरूरतें काफी अलग हैं और विशेषकर 'वित्तीय रूप से समावेशनपरक वृद्धि' को तेज करने के लिए, इसका सर्वव्यापी हल ढूंढ़ना चुनौती भरा हो सकता है।

वित्तीय रूप से समावेशनपरक वृद्धि अपने आप में काफी मुद्दों को समेटे हुए है जिन पर पूर्ववर्ती सत्रों में विस्तार से चर्चा की गई है। मैं इस चुनौती के महत्वपूर्ण आयामों में से एक - 'वित्तीय शिक्षा की चुनौती' तक ही अपनी चर्चा को सीमित रखूंगी।

वित्तीय शिक्षा - संकल्पना

वित्तीय शिक्षा को व्यापक रूप में 'उस प्रक्रिया के रूप में पारिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता /निवेशक वित्तीय उत्पादों, संकल्पनाओं और जोखिमों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं और सूचना, अनुदेश तथा /अथवा वस्तुनिष्ठ सलाह के माध्यम से सूचना / जानकारी के आधार पर अपना विकल्प चुनने/सहायता के लिए कहां जाए यह जानने तथा अपने वित्तीय कल्याण को सुधारने के लिए अन्य प्रभावी कार्रवाई करने के बारे में वित्तीय जोखिमों और अवसरों के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए दक्षताओं और विश्वास को बढ़ाते हैं।' इस प्रकार वित्तीय शिक्षा वित्तीय जानकारी और सलाह के प्रावधान से आगे तक जाती है। वित्तीय शिक्षा पर किसी चर्चा का मुख्य जोर प्रमुखतया व्यक्ति पर होता है, जिसके पास दैनिक आधार पर वैयक्तिक वित्त से जुड़े मामलों पर वित्तीय मध्यस्थकों के साथ वित्तीय लेनदेनों की जटिलताओं को समझने के सामान्यतया सीमित संसाधन और दक्षताएं होती हैं।

वित्तीय शिक्षा बनाम वित्तीय समावेशन की भूमिका

'वित्तीय समावेशन' से संदर्भ में वित्तीय शिक्षा की व्याप्ति तुलनात्मक रूप से व्यापक है और उसे महत्तर महत्व प्राप्त है क्योंकि वित्त के दायरे से अभी तक बाहर रहे समूहों के लिए वित्तीयन तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। इसके अलावा शिक्षण की प्रक्रिया में अनिवार्यतः उन गहरे पैठे व्यवहारगत और मनोवैज्ञानिक कारकों से निपटना भी शामिल है जो प्रमुख बाधायें हो सकती हैं। तथापि, व्यष्टि वित्त तथा वित्तीय शिक्षा के बीच परस्पर अनुपूरक संबंध स्पष्ट है और वित्तीय साक्षरता

* श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 नवंबर 2006 को हैदराबाद में बैंककोन 2006 में विशेष भाषण।

उनके निर्णय करने की शक्ति को बढ़ा सकती है और उन्हें दैनिक जिंदगी की वित्तीय मांगों के साथ गति बनाए रखने के लिए तैयार कर सकती है।

भारत जैसे देशों में जिनमें अलग-अलग प्रकार की सामाजिक और आर्थिक रूपरेखाएं हैं, वित्तीय शिक्षा विशेषकर उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो संसाधनों की दृष्टि से निर्धन हैं, और जो केवल हाशिये पर रहकर परिचालन करते हैं और जो निरंतर निम्नमुखी वित्तीय दबावों के प्रति संवेदनशील हैं। बैंक सुविधा रहित निर्धन लोग, जिनके साथ बैंकों का कोई स्थापित बैंकिंग संबंध नहीं है, खर्चीले विकल्पों की ओर ढकेल दिए जाते हैं। सीमित संसाधनों के साथ कठिन परिस्थितियों में परिवारों के नकदी प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करने के लिए किन का सहारा लिया जाए यह दक्षताओं और जानकारी के अभाव में जानकारी पूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के मार्ग में बाधा बनता है। वित्तीय शिक्षा उन्हें अपनी जीवनचक्र की आवश्यकताओं के लिए समय से पहले ही निर्णय लेने तथा अनावश्यक ऋण का सहारा लिए बिना अप्रत्याशित आपातकाल से निपटने में सहायता कर सकती है।

ओईसीडी के एक अध्ययन[1] के अनुसार बैंक रहित/कम बैंक सुविधा वाले समूहों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों का प्रावधान महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकता है:

- वे बैंक-रहित /कम बैंक सुविधा-प्राप्त उपभोक्ताओं को वित्तीय मुख्य धारा में प्रवेश करने या उनका बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित/ प्रोत्साहित कर सकते हैं ?
- वे कम ही समय में उन्हें सफल खाता धारक बनाए रख सकने में सहायता कर सकते हैं।
- वे उन्हें दीर्घावधि के लिए बचतकर्ता के रूप में बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं ।
- वे परिवारों में आस्ति निर्माण करने में योगदान कर सकते हैं।

वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम बनाने में चुनौतियां

बैंक-रहित /कम बैंक सुविधा वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय शिक्षा की पहलों के कार्यक्रम बनाते समय विद्यमान वित्तीय परिदृश्य इस श्रेणी की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं तथा इस तथ्य को, कि ऐसे समूह में साक्षरता के स्तर निम्न होते हैं, हिसाब में लेना होगा।

निर्धन परिवारों के लिए वित्तीय आयोजना करने में मुख्य अंतर यह है कि उनके पास संसाधन और अवसर कम होते हैं । जब लोग दैनिक आधार पर अपने दो जून की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो धन का बेहतर प्रबंधन करना दैनिक चुनौती बन जाती है। जहां वे अनेक रचनात्मक सीधी-सादी रणनीतियां अपने धन के प्रबंधन के लिए करते रहते हैं, ये रणनीतियां अक्सर गलती करो और सीखो (परीक्षण प्रणाली) द्वारा विकसित की जाती हैं, न कि बनी बनायी पद्धति पर। गरीबों की क्षमता निर्माण में वित्तीय शिक्षा की भूमिका होती है, ताकि वे नियंत्रण प्राप्त कर सकें, सक्रिय बनें, अपनी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सूचना और संसाधनों का उपयोग करें तथा वित्तीय सेवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। जब बेहतर रूप से सूचित ग्राहक वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थागत लाभ के बेहतर उपभोक्ता हो जाते हैं।

इसके अलावा, जैसाकि पहले कहा गया है, शिक्षा देने की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं, - गहरे पैठे व्यवहारपरक और मनोवैज्ञानिक कारकों से निपटना जो प्रमुख बाधक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ''सामूहिक देयता'' की संकल्पना पर कार्य कर रही व्यष्टि वित्त संबंधी विभिन्न पहलों में यह भारी चुनौती हो सकती है कि ऐसी अवस्था के लिए बुनियादी तर्क-सम्मतता को सही माना जाए। जो अन्य बचतों की आदत को शुरू कराते हुए उन्हें ''सामूहिक उत्तरदायित्व'' की संकल्पना को समझने तक ला सकें।

मेक्सिकन अनुभव के बारे में किये गये एक अध्ययन[2] ने यह रेखांकित किया है कि वित्तीय परिदृश्य में जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक कारक वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। परिणाम ये दर्शाते हैं कि भौतिक संसाधनों के अलावा, सामाजिक संबंधों का अंतर्निहित स्वरूप तथा सामुदायिक संबंधों ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उनके उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। वित्तीय सूचना, ज्ञान, अनुभव, अभिवृत्ति का रूपांतरण तथा वित्तीय शिक्षा में सामाजिक संबंध तथा उन्नयन इस अति संवेदनशीलता को कम करने में उल्लेखनीय संसाधन बनते हैं। इसके आधार पर हम यह सुझाते हैं कि वित्त की संस्कृति व्यक्तियों की परिवर्तन और विकास के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बनती हैं।

यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि वित्तीय शिक्षा व्यवहार के सुधार में भी योगदान कर सकती है, परंतु अनेक कारक हैं जो व्यक्ति के वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आम विश्वास के विपरीत, प्रेरणा अंदर से उत्पन्न की जाती है, और इसे निरंतर रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कम से कम किसी बाह्य कारक द्वारा तो नहीं। वित्तीय शिक्षा का सबसे बड़ा अवरोधक है - व्यक्तियों को इसके लिए प्रेरित करना। दूसरे शब्दों में, वित्तीय शिक्षा अनिवार्य रूप से व्यक्तियों को प्रेरित नहीं करती, बल्कि प्रेरणा व्यक्तियों को वित्तीय शिक्षा की ओर ले जाती है। यहां ग्राहकों के वित्तीय सलाहकार के रूप में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

---

1 इम्प्रूविंग फाइनेंन्सियल लिटरेसी : इनलाइसेंसिग ऑफ इश्यूज एण्ड पोलिसीज़ ओईसीडी 2005।

2 *अतिसंवदेनशीलता को कम करने के साधन के रूप में वित्तीय सेवाएं, मेक्स निनो- जाराजुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ।*

संभावित विषय

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद बुनियादी विषयों / मुद्दों के सेट तक पहुंचना संभव हो सकता हैं। जो वित्तीय शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी रूप से निपटाए जा सकते हैं। एक माइक्रो इन्टर प्राईज संसाधन केंद्र द्वारा संचालित 'व्यष्टि वित्त के अवसरों के द्वारा निर्धनों के लिए वित्तीय शिक्षा'[3] परियोजना के अंतर्गत किए गए एक अध्ययन के अनुसार वित्तीय शिक्षा के निम्नलिखित व्यापक विषयों के लिए निरंतर मांग पाई गई :

- मुद्रा प्रबंध : सक्रिय रूप से मुद्रा का प्रबंध कैसे किया जाए;
- ऋण प्रबंध : ऋण को नियंत्रित कैसे किया जाए तथा अतिऋणग्रस्तता से कैसे बचा जाए;
- बचतों का प्रबंध : नियमित रूप से तथा एक सुरक्षित स्थान पर कैसे बचत की जाए;
- वित्तीय वार्ताएं : निविष्टि आपूर्तिकर्ताओं अन्य पारिवारिक सदस्यों तथा वित्तीय संस्थाओं की तुलना में ग्राहकों की मोलभाव करने की स्थिति को कैसे मजबूत बनाया जाए;
- बैंक सेवाओं का उपयोग; बैंक कैसे काम करते हैं और प्रभार लगाते हैं; ग्राहक किस प्रकार बैंक सेवाओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं? बैंकों के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया कर सकते हैं तथा एटीएम का प्रभावी रूप से कैसे प्रयोग कर सकते हैं?

ओईसीडी देशों में ऐसे कार्यक्रमों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अनेक शिक्षा कार्यक्रम विशिष्ट वित्तीय सेवाओं के प्रावधानों से समन्वित हैं जैसे पहला या बुनियादी बैंक खाता, जांच करने और बचत खाते और उनसे मिलती-जुलती बचत योजनाएं, जबकि अन्यों ने एक व्यापक स्वतंत्र दृष्टिकोण को अपनाया, बजट बनाने, बचत करने तथा ऋण प्रबंधन की शिक्षा देने आदि जिनका किसी सेवा उत्पाद के साथ कोई संबंध नहीं था। इनके उद्देश्य भी जनसंख्या के अधिकांश भाग के अनुसार भिन्न-भिन्न थे।

- आम तौर पर बैंक रहित जनसंख्या के लिए उद्देश्य हैं - उद्देश्यों को स्पष्ट करने तथा बैंक खाते के स्वामित्व और सेवाओं को उपयोग या बुनियादी वित्तीय साक्षरता की दक्षताएं बनाना,
- निम्न/मध्यवर्गीय आय वाले कम सुविधाओं वाले उपभोक्ताओं के लिए, अधिकांश कार्यक्रम आम तौर पर मुद्रा और ऋण प्रबंधन पर सलाह देते हैं; जबकि अन्यों का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है तथा बचतों, आस्ति-निर्माण तथा घर का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं से संबंधित होते हैं।

इन पहलों का उद्देश्य है - सुख सुविधाओं से वंचित समुदायों को प्रेरित और स्थिर बनाने के लिए उनका आर्थिक सशक्तीकरण तथा दीर्घावधिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना।

भारतीय संदर्भ

देश के बदले हुए वित्तीय परिदृश्य में वित्तीय शिक्षा को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। जहां एक ओर उसने भावी सामूहिक वृद्धि के नए अवसर प्रस्तुत कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर, इसने कुछ हलकों में अनिश्चितताओं के भयों को भी रेखांकित किया है, मुख्यतः व्यक्तिगत वित्तों तथा जोखिमों के समूह के प्रबंधन में बढ़ते हुए विविध प्रकार के विकल्पों और आप्शंस के कारण। समावेशन परक वृद्धि के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, और इस दिशा में, बैंकिंग क्षेत्र से अपनी भूमिका अदा करने की आशा की जाती है। वित्तीय समावेशन की दिशा में अब तक की गई पहलें इस दिशा में छोटा-सा कदम है। वित्तीय शिक्षा आदर्शतः लंबी अवधियों के लिए दक्षता निर्माण के अनुपूरक का कार्य कर सकती है।

कुछ मुद्दे

वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी के रास्ते में एक प्रमुख बाधा है - बुनियादी शिक्षा की कमी तथा बैंकों से उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी। यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि यूनाइटेड किंगडम का वित्तीय समावेशन कार्यदल, जो वित्तीय समावेशन की बात करने में अग्रणी रहा है, ने 'फेस-टू-फेस निःशुल्क मुद्रा सलाह' को वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण घटक माना है जो बैंकिंग तक पहुंच तथा 'वहनीय ऋण तक पहुंच' के अलावा है। जनता को सूचना और सलाह की जरूरत होती है जब वे अपने धन की बचत करते हैं या ऋण में फंस जाते हैं। ऐसी सूचना तथा मार्गदर्शन उपयुक्त प्रक्रिया तंत्र द्वारा दी जा सकती है, और यदि ऐसा प्रभावी प्रक्रिया तंत्र बैंकों द्वारा स्थापित किया जाता है, तो वे इसके बदले में वित्तीय सेवाओं के लिए मांग को बढ़ाएंगे।

अन्य बाधा है - आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दों से निपटने में कठिनाईयां सूचना की कमी। समन्वित प्रयासों के बावजूद पारदर्शिता की वर्तमान स्थिति तथा ग्राहकों द्वारा बेहतर सूचना को पहचानने और समझने में कठिनाई वित्तीय मध्यस्कों तथा ग्राहकों के बीच सूचना की विषमता की ओर ले जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की जागरूकता की कमी स्वयं में एक जोखिम जैसा ही है और चुनौती यह है कि ग्राहकों को विभिन्न जोखिमों के प्रति जागरूक बनाया जाए। वित्तीय समावेशन को प्रौन्नत करने की दृष्टि से काफी कुछ कार्य एक सुरक्षित और व्यस्त परिवेश में आसानी से बोधगम्य सूचना प्रदान करना है।

---

[3] वित्तीय शिक्षा : ए विन -विन फॉर क्लाऐंट्स एण्ड एमएफआईज़, कोहन, एम स्टेक, के.एण्ड मेक्ग्यूनीज, इ।
http://www.microfinanceopportunities.org/docs/Financial_Education_A_Win_Win_for_Clients_and_MFIs.pdf

वित्तीय शिक्षा के लिए गुंजाईश

निर्धनों के लिए विकास नीतियों तथा अतिसंवेदनशीलता को कम करने और अवसर बढ़ाने के संदर्भ में वित्तीय शिक्षा को प्रौन्नत करने के लिए निस्संदेह एक भूमिका है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों जैसे व्यष्टि वित्त, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, कारोबारी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ वित्तीय साक्षरता को समन्वित करने की संभावनाओं को तलाशने की जरूरत है। 1990 के बाद के दशक के उत्तरार्ध में ब्रिटेन और अमरीका में एक प्रयास किया गया कि सभी सरकारी भुगतान इलैक्ट्रोनिक द्वारा किए जाएं जिसने वित्तीय बहिष्करण की महत्ता को बढ़ाने को नीतिगत चिंता बना दिया। इलैक्ट्रोनिक रूप से सरकारी भुगतान किए जाने से भुगतान तथा अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का होना अनिवार्य बना दिया गया । इसने बैंक सुविधा रहित ग्राहकों के लिए और भी महत्वपूर्ण बना दिया कि वे बुनियादी बैंक खातों, बचत बैंक खातों तथा अन्य वित्तीय सेवाओं पर सूचना तक पहंच बनाए रखें। वित्तीय सेवाओं पर सूचना प्राप्त करने के लिए वित्तीय शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की अपेक्षा होगी।

उदाहरण के लिए भारत में भी उन्नत प्रौद्योगिकी सरकारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले सभी भुगतानों को इलैक्ट्रोनिक रूप में करने में समर्थ बनाएगी। मैं समझती हूं कि आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने ई-सेवा के माध्यम से भुगतान करने की पहल की है। अन्य राज्यों ने भी ऐसी पहलें शुरू की हैं। सरकारों को इस बात की संभावना तलाशनी चाहिए कि बैंक खातों में सीधे जमा किया जाए। अंततः हिताधिकारी द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों के भाग तथा बैंक के पास रखी गई जमाराशियां ऐसे हितकारियों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए बीज-पूंजी का भाग बन सकती हैं।

जहां कुछ बैंकों ने ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी ओर से कदम उठाये हैं, वहीं भारी मात्रा में वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी पहलों के अलावा, जहां भी उपलब्ध हों अन्य एजेंसियों जैसे निजी संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी संगठन, सहकारी क्षेत्र के बिक्री केंद्र आदि की विशेषज्ञता तथा अनुभव का लाभ उठाने की जरूरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वित्तीय साक्षरता और शिक्षा प्रदान करने में काफी अवसर प्रदान करता है तथा ग्रामीण सूचना कोईस्क, मोबाइल वैन आदि के माध्यम से देश के अनेक भागों में हुए अनुभवों ने यह दर्शाया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर सूचना प्रदान करने में किस सीमा तक सहायक हो सकती है। सूचना कोईस्क कारोबारी प्रतिनिधियों द्वारा या स्थापित पीसीओ आदि द्वारा चलाए जा सकते हैं जो न केवल बैंकिंग उत्पादों, बल्कि ऐसी अन्य सूचनाएं भी जैसे निविष्टि /उत्पाद मूल्यों, बीमा उत्पादों, स्वास्थ्य सेवाओं, मौसम संबंधी सूचना आदि के बारे में भी सूचनाएं प्रसारित कर सकते हैं। ऋण स्वीकृत करते समय इस प्रकार की जानकारी, जोखिमों से बेहतर रूप से निपटने, दस्तावेजीकरण संबंधी झंझटों को कम करने आदि में सहायक हो सकती है। कोईस्क के लिए किसी कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं होती है और सेवा देनेवाला व्यक्ति अधिकांश जानकारी को इलैक्ट्रोनिक मीडिया जैसे सीडी के जरिये अद्यतन कर सकता है। ऐसे कोईस्क की स्थापना और उनको चलाने की लागत को पूरा करने के लिए बैंक निधियां प्रदान कर सकते हैं अथवा यह लागत बैंकों तथा इस प्रक्रिया में जुड़े उच्च संगठनों द्वारा आपस में बांटी जा सकती है।

कुछ गैर-बैंकिंग पहलें भी देश के विभिन्न भागों में अनुभव की जा रही हैं। इस संदर्भ में भारत में स्व-रोजगार में लगी निर्धन महिलाओं के लिए 'सेवा' द्वारा शुरू की गई वित्तीय मंत्रणा सेवा पर परियोजना काफी प्रसिद्ध है। भारत में 2001 में शुरू की गई 'प्रोजेक्ट टूमोरो', जैसा कि इसका नाम है, का प्रयोजन था - धन का उत्पादक रूप में प्रबंधन करने, आस्तियों में वृद्धि करने के तरीकों की योजना बनाने, जीवन चक्र की घटनाओं से निपटने तथा जोखिमों का प्रावधान करने में सहभागियों की सहायता करने के लिए वित्तीय मंत्रणा देने वाले पाठ्यक्रम का विकास करना और उसका परीक्षण करना। इस परियोजना के माध्यम से, 'सेवा' ने एक प्रशिक्षण इकाई तथा प्रशिक्षण देने की प्रणाली स्थापित की है तथा वह परामर्शन / या मंत्रणा कार्य की निगरानी करने के लिए साधन और प्रक्रियाएं विकसित कर रहा है। परियोजना सेवा के ग्राहकों के बीच वित्तीय शिक्षा के लिए जरूरतों और मांग का आकलन करने के लिए बाजार-अनुसंधान से शुरू हुई और उसके बाद प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया गया। यह सेवा साप्ताहिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने ग्राहकों को वित्तीय मंत्रणा प्रदान कर रही है। प्रारंभिक अनुभव यह सुझाते हैं कि सहभागी प्रस्तुत संकल्पना को समझते हैं तथा इस प्रकार के प्रशिक्षण से निकलनेवाली नई संभावनाओं का स्वागत करते हैं।

व्याप्ति का विस्तार करना

- वित्तीय शिक्षा की बात करते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि इस ध्यान का जोर शहरी जनता की ओर भी बढ़े जिसमें साक्षर लोगों को भी शामिल किया जाए जिसके पास अभी भी वित्तीय कुशाग्र बुद्धि, प्रौद्योगिकीगत विशेषज्ञता, नहीं है और जो वित्तीय रूप से 'शिक्षित' नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि शहरी आम जनता इन्टरनेट बैंकिंग तथा बैंकिंग की अन्य नई-नई पद्धतियों से सुपरिचित हो ही। अभी भी शहरों में एक जनसंख्या घटक बना हुआ है, जो अभी भी या तो आत्मविश्वास की कमी के कारण इन सेवाओं का उपयोग करने से बच रहा है या वह उपलब्ध विकल्पों से अनजान है। ऐसे लक्ष्यबद्ध समूह के लिए वित्तीय शिक्षा परस्पर हितकारी होगी।
- बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विविध उत्पादों और सेवाओं के बारे में और ज्यादा जानकारी देने की भी जरूरत है। ऐसा ही एक विशेष उदाहरण मेरे ध्यान में आ रहा है जो आवास वित्त के क्षेत्र का

है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी अपनी हाल की मौद्रिक नीति की मध्यावधिक समीक्षा में आवासीय ऋणों के बारे मे ंपारदर्शिता और ईमानदारी का मुद्दा उठाया था। यह रिपोर्ट मिली है, कि कुछ बैंक, आवास के लिए ऋण देते समय, सचल दरों (प्लोटिंग रेट) तथा पुनः निर्धारण शर्त के बारे में आधार दर को संचालित करने वाले कारकों को बताने में पूर्णतः पारदर्शी नहीं हैं। उपभोक्ता जागरूकता के एक भाग के रूप में उधारदाताओं के स्तर पर प्रकटीकरण स्तरों को बढ़ाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं, परंतु इस सबकी प्रभावशीलता उधार लेने वाले व्यक्ति की वित्तीय समझ पर निर्भर करेगी। सच्चा मुद्दा यह है कि क्या उपभोक्ता सचल दर में अंतनिर्हित सिद्धांत को समझता है अथवा क्या वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके साथ लेनदेन करने में बैंक ईमानदार और पारदर्शी रहा है। स्पष्टतः अतिसंवेदनशील उपभोक्ताओं को ''वित्तीय रूप से असंतोषजनक ऋण व्यवस्थाओं'' का शिकार होने से बचाने के लिए वित्तीय शिक्षा की जरूरत है।

विप्रेषण सुविधाओं और विदेशी मुद्रा नकदीकरण के संबंध में विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता की कमी आम जनता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है जो प्रवासी कार्मिकों से आने वाले छोटे-मोटे विप्रेषणों का हिताधिकारी है। हाल ही में, एनआरआई विप्रेषणों की लागत पर कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में विशेषकर प्रवासी कार्मिकों के लिए विप्रेषण करने के लिए विद्यमान सुविधाओं पर बुनियादी जागरूकता देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम 'निरंतर आधार पर चलाने को जरूरत पर जोर दिया है। अन्य बातों के अलावा, यह विप्रेषण भेजने की लागत को भी कम करने में मदद कर सकता है।

- हालांकि 'वित्तीय शिक्षा' शब्द व्यक्तिगत/वैयक्तिक वित्त से जुड़ा हो गया है, परंतु ऐसी पहलों के दायरे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक को लाया जाना चाहिए वह लघु उद्यमियों और छोटे कारोबारियों से भी जुड़ा हो। विशेषकर, जब प्रयास समावेशन की वृद्धि के हो रहे हों तो छोटे शहरों/ कस्बों में ये ही घटक हैं जो आर्थिक वृद्धि के लाभों को वास्तव में दर्शाते हैं। ऐसे मामलों में मुख्य ध्यान का केंद्रबिंदु स्पष्टतः कुछ अलग ही होगा जिसमें मात्र शिक्षा देने के बजाए ज्यादा जोर जागरूकता और वित्तीय सूचना को सही समय पर देने पर रहेगा। इस प्रकार सही समय पर सूचना देना उनके उद्यमों की सफलता या असफलता का निर्णायक कारक बन सकता है। सभी संभावनाओं में, इन लघु उद्यमों की सफलता या असफलता का निर्णायक कारक बन सकता है। सभी संभावनाओं में, इन लघु उद्यमों के प्रवर्तक शिक्षित होंगे ही और उनके पास कारोबारी और कारोबारी विचार/समझ भी पहले से ही होगी, जिन्हें व्यावहारिक रूप में परिणत करने की जरूरत है। यहीं पर नए वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता तथा उनके मूल्य निर्धारण के बारे में समझ उन्हें यह सुनिश्चित करने में समर्थ बना सकती है कि वे उत्पाद की कमियां, उनका वर्तमान और भविष्य समझें तथा उधारदाता के सामने बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में हों।
- अंतिम, वित्तीय शिक्षा की संकल्पना को आदर्शतः बढ़ाकर उसमें आर्थिक शिक्षा को भी शामिल किया जा सकता हैं। एक व्यापक सामाजिक स्तर पर आर्थिक सुधार के पथ को देखते हुए जिसे भारत ने 1990 के बाद के प्रारंभिक वर्षों से पकड़ लिया है, और आगामी चर्चाओं में यह अनिवार्य है कि सोसाइटी और आम जनता को वस्तुनिष्ठ रूप से बुनियादी आर्थिक मुद्दों से तथा इसके पीछे तर्कधार से और कभी-कभी कठिन होता है, इस संबंध में किये जानेवाले चयनों से परिचित कराया जाए। यह प्रयास एक जानकारीपूर्ण तथा समरसतापूर्ण लोक तंत्र के निर्माण में दूर तक जाएगा।

निष्कर्ष

आम जनता को वित्तीय शिक्षा देने का प्रयास करने वाले बैंकों तथा एजेंसियों को यह समझने की जरूरत है कि वित्तीय समावेशन एक निरंतर प्रक्रिया है । शिक्षा देने के प्रयास करके एकबारगी आम आदमी को संबंधित कार्यमूलक, विधि संबंधी तथा तकनीकी मुद्दों से परिचित कराकर समर्थ बना देना पर्याप्त नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है।

शैक्षिक कार्यक्रम विशेषकर 'आपूर्ति' पक्ष पर जोर देते हैं जो ग्राहकों को वित्तीय दायरे में लाने के लिए आकर्षित करने पर जोर देता है। तथापि जरूरत इस बात की है कि एक 'ओटो पाइलेट' की संकल्पना अपनायी जाए जहां संभावित ग्राहक को अपेक्षित सेवाएं देने/मांगने के लिए शक्तिसंपन्न बनाया जाए। यह वित्तीय सेवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण 'मांग' की स्थिति पैदा करा सकती है।

वित्तीय शिक्षा का उदेश्य भी ग्राहक का संरक्षण है। यह वित्तीय जोखिम को बेहतर रूप में समझने तथा बाजार की जटिलताओं से निपटने तथा वित्तीय क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और विकल्पों का लाभ लेने में ग्राहक की सहायता करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी ओर से अपनी समग्र रणनीति के एक भाग के रूप में देशभर में वित्तीय शिक्षा को बढ़ाना चाहता है। वर्तमान में ऋण परामर्शन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो उधारकर्ताओं की और विशेषकर ऐसे उधारकर्ताओं की, जो संकट में हैं, सहायता करें कि वे अपनी वर्तमान वित्तीय समस्याओं पर काबू पा सकें और संरचनागत वित्तीय प्रणाली में पहुंच प्राप्त कर सकें।

तथापि, अंतिम विश्लेषण में, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय साक्षरता को सुधारने तथा वित्तीय सेवाओं तथा पहुंच को बढ़ाने की एक पर्याप्त वित्तीय नीति का केवल एक स्तंभ है। यह अन्य स्तंभों जैसे महत्तर पारदर्शिता, ग्राहक संरक्षण संबंधी नीतियां तथा वित्तीय संस्थाओं के विनियमन की सहायता भर कर सकती है, उनका स्थान नहीं ले सकती । मुझे आशा है कि हमारे सामूहित हित में इस सम्मेलन में उठाए गए मुद्दे क्रियान्वित किए जाएंगे और मूल आधार स्तर पर की जानेवाली पहलों के रूप में रूपांतरित किए जाएंगे।